

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी • इंदौर, उज्जैन और रीवा में पीपीपी मोड से बनाएं आईटी पार्क

मुख्यमंत्री ने कहा- वन क्षेत्रों में शिकार और अवैध कटाई पर ड्रोन तकनीक से रखें नजर

विशेषसंवाददाता | भोपाल



प्रदेश में पेड़ों की अवैध कटाई, अवैध खनिज उत्खनन और वन क्षेत्रों में शिकार पर लगातार लगाने के लिए सरकारी विभाग ड्रोन तकनीक का इस्तेमाल शुरू करें। इसके अलावा सघन बस्तियों में निगरानी के लिए पुलिस भी ड्रोन तकनीक का उपयोग बढ़ाए। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने यह निर्देश मंगलवार को मंत्रालय में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की गतिविधियों की समीक्षा के दौरान दिए। बैठक में मुख्य सचिव अनुराग जैन भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पीपीपी मोड से आईटी पार्क बनाए जाएं। इंदौर, उज्जैन और रीवा में इसकी संभावनाएं हैं, जिसे साकार किया जाए। सभी आईटी प्रोजेक्ट्स के काम पूरे करने के लिए समय तय करें। नर्मदा नदी के तटीय क्षेत्रों, फसलों की रक्षा और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए नई तकनीकों का प्रभावी उपयोग करने पर भी उन्होंने जोर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उज्जैन जिले की डोंगला ऑब्जर्वेटरी को आईआईटी इंदौर के साथ जोड़कर रिसर्च और डेवलपमेंट पाठ्यक्रम विकसित करने चाहिए।

साइबर सुरक्षा के लिए एमपी एसईडीसी को जिम्मेदारी

मुख्यमंत्रीने सभी विभागों में एमपी एसईडीसी के जरिए साइबर सुरक्षा की डीपीआर बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सिंहस्थ-2028 के लिए भी नगरीय प्रशासन विभाग के आईटी प्रोजेक्ट्स की जिम्मेदारी एमपी एसईडीसी को दी जाएगी। इसके लिए एमपी एसईडीसी अभी से प्लान बनाकर काम शुरू करे। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग सक्षम बने और अलग-अलग प्रोजेक्ट की साइबर सुरक्षा के लिए भी काम करें।

अंतरिक्ष विज्ञान पढ़ाने व

अनुसंधान पर फोकस

मुख्यमंत्री ने छात्र-छात्राओं को अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में अध्ययन और अनुसंधान के लिए प्रेरित करने के निर्देश दिए। स्कूल-कॉलेज के छात्र-छात्राओं को ऑब्जर्वेटरी का भ्रमण करवाएं ताकि उनके ज्ञान का स्तर बढ़ सके। उन्हें मौजूदा दौर से जोड़ने के लिए उनके बौद्धिक स्तर को बढ़ाना जरूरी है। बैठक में उन्हें बताया गया कि इस साल उज्जैन तारामंडल में 8 करोड़ की लागत से अपग्रेडेशन के काम हुए हैं। यहाँ थ्रीडी 4-के प्रोजेक्शन सिस्टम शुरू होने के बाद 400 से ज्यादा शो किए गए हैं।

6 पुराने सरकारी कॉलेज आईआईटी की तर्ज पर विकसित किए जाएं

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के 6 पुराने शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालयों को आईआईटी की तर्ज पर विकसित किया जाए। जरूरत पड़ने पर इन कॉलेजों को विकसित करने के लिए उद्योग विभाग की भी मदद ली जाए। सभी शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज को आईटी डिपार्टमेंट से समन्वय स्थापित कर विकसित किया जाए। बैठक में मुख्य सचिव अनुराग जैन ने भी पीपीपी मोड पर आईटी पार्क विकसित करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि पुलिस विभाग में अलग-अलग स्थानों का डेटा इंटीग्रेट कर हीट मैप बनाएं। इससे अपराध का विश्लेषण हो सकेगा और अपराधों में कमी लाने पर काम किया जा सके।